सतीश कुमार मित्तल, न्यायमूर्ति के समक्ष

ईशम सिंह और अन्य, - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य, - प्रतिवादी

Crl. R. No. 143 of 2004

20 फरवरी, 2004

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा. 319-याचिकाकर्ताओं समेत आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज -जांच में पुलिस ने याचिकाकर्ताओं को अपराध में शामिल नहीं पाया -याचिकाकर्ताओं के खिलाफ -सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक आवेदन पर कोई चालान दायर नहीं किया गया । शिकायतकर्ता द्वारा दायर पी.सी., ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया-उसे चुनौती अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में साक्ष्य याचिकाकर्ताओं को अपराध के कमीशन से नहीं जोड़ता है-केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता को विशिष्ट चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, इसमें संलिप्तता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है अपराध में याचिकाकर्ताओं-ट्रायल कोर्ट के आदेश याचिकाकर्ताओं को तलब करने के लिए उत्तरदायी हैं।

माना गया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत यह राय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि याचिकाकर्ताओं ने कथित अपराध किया है। केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता ने पीडब्लू 3 के रूप में पेश होते हुए याचिकाकर्ताओं को विशिष्ट चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपराध में शामिल थे, खासकर जब शिकायतकर्ता का यह संस्करण उसके पहले लिखित संस्करण और तथ्य में सुधार था कि पार्टियों के बीच दुश्मनी थी। मौजूदा मामला ऐसा नहीं था जहां ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ताओं को एक अतिरिक्त आरोपी के रूप में

बुलाने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के कमजोर सबूतों को ध्यान में रखते हुए जो याचिकाकर्ताओं को अपराध के कमीशन से नहीं जोड़ता है। याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने से कोई आपराधिक न्याय हासिल नहीं होगा। बल्कि जो लोग अपराध में शामिल नहीं थे, उन्हें फंसाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस गिल और एच सी राही अधिवक्ता।

सुनील के वशिष्ठ एएजी हरियाणा, प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

सतीश कुमार मित्तल, न्यायमूर्ति.

(1) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरुक्षेत्र द्वारा पारित 9 अक्टूबर, 2003 के आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ईशम सिंह, चरणा और सराबा ने उक्त आदेश को रद्द करने के लिए यह याचिका दायर की है, जिसके तहत उन्हें बुलाया गया है। एक अतिरिक्त आरोपी को चार और आरोपियों के साथ.आईपीसी की धारा 323, 324, 325, 326 और 34 के तहत मुकदमे का सामना करना होगा।

(2) इस मामले में, जोधा राम नामक व्यक्ति की लिखित शिकायत पर, पुलिस स्टेशन, पिहोवा में उपरोक्त धाराओं के तहत सात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता और आरोपी की कृषि भूमि एक-दूसरे से सटी हुई है। कीटनाशकों के छिड़काव के कारण आरोपियों के मन में कुछ गलतफहमी हो गई थी. उस खाते पर, एक दिन. यानी 18 मार्च 2001 को सभी आरोपी घातक हथियारों से लैस होकर शिकायतकर्ता के घर के सामने गली में आये और गाली-गलौज करने लगे. जब शिकायतकर्ता ने पूछा कि वे उसे गाली क्यों दे रहे हैं। इस पर सभी आरोपियों ने ललकारा उठाया और परिवादी के शरीर पर लाठी, कुल्हाड़ी व सरिया से वार करना शुरू कर दिया. आरोपियों ने उसके पैर, सिर,

पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें पहुंचाईं और पैर में फ्रैक्चर भी हुआ। शिकायतकर्ता ऊंची आवाज में चिल्लाई, जिस पर शिकायतकर्ता की पत्नी जगदीश, राम सिंह और संतोष मौके पर आए और शिकायतकर्ता को आरोपियों के क्रूर चंगुल से बचाया। इसके बाद सभी आरोपी शिकायतकर्ता को निकट भविष्य में जान से मारने की धमकी देकर अपने-अपने हथियारों सहित मौके से भाग गए।

(3) शिकायत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत संदर्भित की गई थी। पी.सी. के आधार पर उपरोक्त एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की गयी. पूछताछ करने पर, पुलिस ने पाया कि तीनों याचिकाकर्ता अपराध में शामिल नहीं थे और चालान केवल चार लोगों के खिलाफ दायर किया गया था जिनके पास से हथियार बरामद किए गए थे और जो पुलिस जांच के अनुसार अपराध में शामिल थे।

(4) इलाक़ा मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया मामला पाया और चारों आरोपियों पर आरोप पत्र दायर किया। अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य में राम सिंह, पीडब्लू-1, चश्मदीद गवाह एएसआई राम पाल-पीडब्लू 2 और जोधा राम से पूछताछ की। शिकायतकर्ता-पीडब्लू 3. उस स्तर पर, शिकायतकर्ता द्वारा धारा 319 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। याचिकाकर्ताओं को शेष आरोपियों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाने के लिए. उक्त आवेदन को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा आक्षेपित आदेश के तहत अनुमति दी गई थी।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने के लिए अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाते समय अवैध रूप से कार्य किया है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य से यह प्रतिबिंबित नहीं होता है कि याचिकाकर्ताओं ने अपराध किया था अपराध. अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के तीन चश्मदीद गवाह थे, राम सिंह, जगदीश और श्रीमती। संतोष. तीन चश्मदीदों में से सिर्फ राम सिंह का बयान दर्ज कराया गया. पीडब्लू 1 के रूप में अपने बयान में, राम सिंह ने अभियोजन पक्ष के संस्करण का समर्थन नहीं किया और उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। विवादित आदेश पारित होने से पहले अन्य दो कथित चश्मदीदों के बयान दर्ज नहीं किए गए थे। हालाँकि,

एक अन्य स्वतंत्र चश्मदीद गवाह, जिसका नाम जगदीश है, ने धारा 161 सीआपीसी. के तहत पुलिस के सामने अपने बयान में कथित अपराध के लिए किसी भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं बताया। अभियोजन पक्ष द्वारा जांचा गया दूसरा गवाह पीडब्लू 2, एएसआई राम पाल है।इस गवाह ने कथित अपराध के लिए किसी याचिकाकर्ता का नाम भी नहीं लिया है। उनके मुताबिक उनकी जांच में तीनों याचिकाकर्ता घटना में शामिल नहीं थे. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं से अपराध में इस्तेमाल किए गए किसी भी हथियार की कोई बरामदगी नहीं हुई। सभी हथियार चारों आरोपियों के कब्जे से बरामद किए गए, जो पुलिस जांच के अनुसार अपराध में शामिल थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी जांच के अनुसार, शिकायतकर्ता ने तीन याचिकाकर्ताओं का झूठा नाम लिया है। तीसरा गवाह, जिसकी अभियोजन पक्ष ने जांच की, वह जोधा राम-शिकायतकर्ता है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि सातों आरोपी सामूहिक रूप से उनके घर के सामने आये और गाली-गलौज करने लगे. जब उसने उन्हें गाली देने से रोकने को कहा तो सभी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। इसके बाद, इस गवाह ने याचिकाकर्ताओं सहित अभियुक्तों को विशिष्ट चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रत्येक आरोपी को विशिष्ट चोट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना एक सुधार है, क्योंकि, शिकायत में, याचिकाकर्ताओं सहित किसी भी आरोपी को कोई विशिष्ट चोट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था।

(6) उपरोक्त साक्ष्यों का उल्लेख कर अभियोजन अभिलेखित किया गया जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने के लिए एक अतिरिक्त अभियुक्त के रूप मेंबुलाया गया है, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं और शिकायतकर्ता के परिवारों के बीच दुश्मनी थी और उस उद्देश्य से, शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के सभी सात परिवार के सदस्यों को गलत तरीके से शामिल किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन पक्ष के मामले

का समर्थन नहीं किया है। यहां तक कि जांच अधिकारी ने अदालत के समक्ष कहा है कि उनकी पूछताछ के अनुसार, याचिकाकर्ता घटना के समय उपस्थित नहीं थे और शिकायतकर्ता ने उन्हें अप्रत्यक्ष उद्देश्य से झूठा फंसाया है। एकमात्र साक्ष्य, जिसके आधार पर, याचिकाकर्ताओं को बुलाया गया है, शिकायतकर्ता-जोधा राम के बयान का उक्त भाग है, जहां उन्होंने विशेष रूप से विशिष्ट चोटों वाले याचिकाकर्ताओं का नाम लिया है। बयान का यह हिस्सा स्पष्ट रूप से लिखित शिकायत में उल्लिखित पहले संस्करण में सुधार है, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। बयान का उक्त भाग याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने माइकल मचाडो और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (1) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और डॉ. संत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2).मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

(7) दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट ने उसके समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के आधार पर याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए उचित आदेश पारित किया है। कहा कि आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

(8) मैंने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें सुनी हैं। सीआरपीसी की धारा 319 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए एक अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के संबंध में कानूनी स्थिति। आरोप नहीं लगाया गया है, ने एक अपराध किया है जिसके लिए उस व्यक्ति पर पहले से ही आरोपित अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है।

(1) 2002 (2) आर.सी.आर. (आपराधिक) 75(2) 2002

(2) आर.सी.आर. (आपराधिक) 719

की संलिप्तता के बारे में कुछ संदेह मान लिया। यह पर्याप्त नहीं है कि न्यायालय ने साक्ष्यों से अपराध में किसी अन्य व्यक्ति. अच्छी तरह से व्यवस्थित है, संयमित रूप से और मुख्य रूप से आपराधिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए न्यायालय को धारा 319 सीआरपी.सी के तहत शक्ति का उपयोग करना होगा। लेकिन शिकायतकर्ता के हाथों उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए एक हैंडल के रूप में नहीं जो अपराध के कमीशन में शामिल नहीं है। माइकल मचाडो के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित इस धारा को लागू करने के लिए आधार की आवश्यकता यह है कि यह मुकदमे के दौरान या पूछताछ में एकत्र किए गए सबूतों से अदालत के सामने आना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति, जिस पर उस मामले में अभियुक्त के रूप में दूसरे शब्दों में, न्यायालय को दो पहलुओं के संबंध में पहले से एकत्र किए गए साक्ष्य से उचित संतुष्टि होनी चाहिए। पहला यह कि दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया है और दूसरा यह कि ऐसे अपराध के लिए दूसरे व्यक्ति पर भी पहले से ही आरोपित आरोपी के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन यह हमेशा न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है क्योंकि कानून में "न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है" शब्दों का उपयोग किया गया है। इस प्रकार प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल आपराधिक न्याय प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब भी न्यायालय को किसी अन्य व्यक्ति को भी अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य मिलते हैं तो उसे उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाना चाहिए। जिस चरण पर मुकदमा पहले ही आगे बढ़ चुका है और तब तक एकत्र किए गए सबूतों की मात्रा सहित मामले की रूपरेखा तैयार करने के लिए न्यायिक अभ्यास की आवश्यकता होती है।

(9) इस मामले के तथ्यों पर आते हुए, मेरी राय में, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत यह राय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि याचिकाकर्ताओं ने कथित अपराध किया है। केवल, क्योंकि शिकायतकर्ता ने पीडब्लू 3 के रूप में पेश होते हुए याचिकाकर्ताओं को विशिष्ट चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपराध में शामिल थे, खासकर जब शिकायतकर्ता का यह संस्करण उसके पहले

लिखित संस्करण में सुधार था और तथ्य यह है कि पार्टियों के बीच दुश्मनी थी। मेरी राय में, जो मामला सामने आया है वह ऐसा नहीं है जहां ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ताओं को एक अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुलाने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के कमजोर सबूतों को ध्यान में रखते हुए जो याचिकाकर्ताओं को आयोग से नहीं जोड़ता है। अपराध का. मेरे विचार में याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में तलब करने से कोई आपराधिक न्याय हासिल नहीं होगा। बल्कि जो लोग अपराध में शामिल नहीं थे, उन्हें फंसाना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

(10) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित 9 अक्टूबर, 2003 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के आदेश को बहाल किया जाता है।

R.N.R.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी